



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ३३]

मंगळवार, सप्टेंबर १५, २०१५/भाद्रपद २४, शके १९३७

[पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५८

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

नगर विकास विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक २९ अगस्त २०१५ ।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XVII OF 2015.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN
PLANNING ACT, 1966.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १७ सन् २०१५ ।

महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी
अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

सन् १९६६ और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके
का महा. कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में
३७। अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब इसलिये, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुये, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

सन् १९६६ १. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ संक्षिप्त नाम तथा
का महा. कहलाए । प्रारंभण ।
३७ ।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

(१)

- सन् १९६६ का
महा. ३७ की
धारा ४० में
संशोधन।
२. महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (जिसे इसमें आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा ४० की उप-धारा (३) के खण्ड (ड) में, “भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४” शब्दों तथा अंकों के स्थान में, “भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ के उपबंधों के अधीन” शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा।
- सन् १९६६ का
महा. ३७ की
धारा ११३क में
संशोधन।
३. मूल अधिनियम की धारा ११३क में, “भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अधीन” शब्दों तथा अंकों के स्थान में, “भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ के उपबंधों के अधीन” शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा।
- सन् १९६६ का
महा. ३७ की
धारा ११६ में
संशोधन।
४. मूल अधिनियम की धारा ११६ में, “भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अधीन” शब्दों तथा अंकों के स्थान में, “भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ के उपबंधों के अधीन” शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा।
- सन् १९६६ का
महा. ३७ की
धारा १२५ में
संशोधन।
५. मूल अधिनियम की धारा १२५ में,—
- (एक) “भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अर्थात्गत” शब्दों तथा अंकों के स्थान में, “भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ के अर्थात्गत” शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा।
- (दो) निम्नलिखित परंतुक, जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—
- “परंतु, भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ की धाराएँ ४ से १५ में (दोनों को सम्मिलित करके) विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, ऐसी भूमियों के संबंध में लागू नहीं होगी।”
- सन् १९६६ का
महा. ३७ की
धारा १२६ में
संशोधन।
६. मूल अधिनियम की धारा १२६ में,—
- (एक) उप-धारा (१) के,—
- (क) खण्ड (ख) में, “भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ में अधिकथित सिद्धांतों के आधार पर” शब्दों तथा अंकों के स्थान में, “भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ के सिद्धांतों के आधार पर” शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा।
- (ख) खण्ड (ग) में, “भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अधीन” शब्दों तथा अंकों के स्थान में, “भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता के अधिकार के उपबंधों के अधीन” शब्द तथा अंक रखे जाएँगे;
- (ग) “या भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अधीन” शब्दों के स्थान में, “या भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित तथा पारदर्शकता के अधिकार अधिनियम, २०१३ के अधीन” शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा;
- (दो) उप-धारा (२) में, “भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धारा ६ में उपबंधित रीत्या में” शब्दों तथा अंकों के स्थान में, “भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता के अधिकार अधिनियम, २०१३ की धारा १९ में उपबंधित रीत्या में” शब्द तथा अंक रखे जाएँगे;
- (तीन) उप-धारा (३) में, “धारा ६” शब्द तथा अंक के स्थान में, “धारा १९” शब्द तथा अंक रखे जाएँगे;
- (चार) उप-धारा (४) में, “भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अधीन” शब्दों तथा अंकों के स्थान में, “भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ के अधीन” शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा।

७. मूल अधिनियम की धारा १२७ की, उप-धारा (१) में, “ बारह महिने ” शब्दों के स्थान में “ चौबीस महिने ” शब्द रखे जाएँगे ।

सन् १९६६ का
महा. ३७ की
धारा १२७ में
संशोधन ।

८. मूल अधिनियम की धारा १२८ की,—

सन् १९६६ का
महा. ३७ की
धारा १२८ में
संशोधन ।

सन् १८९४
का १ ।
सन् २०१३
का ३० ।
(एक) उप-धारा (१) में, “ भूमि अर्जन, अधिनियम, १८९४ के उपबंधों के अधीन ” शब्दों तथा अंकों के स्थान में, “ भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ के उपबंधों के अधीन ” शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा ;

सन् १८९४
का १ ।
सन् २०१३
का ३० ।
(दो) उप-धारा (२) में, “ भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के उपबंधों के अधीन ” शब्दों तथा अंकों के स्थान में, जहाँ कहीं वे दोनों स्थानों पर आते हों, वहाँ, “ भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ के अधीन ” शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा ;

सन् १८९४
का १ ।
सन् २०१३
का ३० ।
(तीन) उप-धारा (३) में, “ भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धाराएँ १६ या १७ ” शब्दों तथा अंकों के स्थान में, “ भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ की धाराएँ ३८ या ४० ” शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा ।

९. मूल अधिनियम की धारा १२९ में,—

सन् १९६६ का
महा. ३७ की धारा
१२९ में संशोधन ।

(एक) उप-धारा (१) में,—

(क) “ उस प्राधिकरण द्वारा लोकहित में ” शब्दों के स्थान में, “ राज्य सरकार के अनुमोदन से उस प्राधिकरण द्वारा, भारत की रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या प्राकृतिक आपदाओं के लिए या किसी अन्य आपात स्थिति के लिए ” शब्दों को रखा जाएगा ;

सन् १८९४
का १ ।
सन् २०१३
का ३० ।
(ख) परंतुक्त में, “ भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धारा, २४ में ” शब्दों तथा अंकों के स्थान में, भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ की धारा २८ में ” शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा ;

सन् २०१३
का ३० ।
(दो) उप-धारा (२) में, “ प्रतिकर की रकम पर, प्रतिवर्ष ४ प्रतिशत ब्याज ” शब्दों तथा अंकों के स्थान में, “ भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता के अधिकार अधिनियम, २०१३ के उपबंधों के अनुसार ब्याज तथा अन्य प्रतिकर ” शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा ;

वक्तव्य ।

महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ का महा. ३७), वह नगर योजना एक स्कीमों को उचित रीत्या में बनाने और उसका कार्यान्वयन प्रभावी रूप से करने की सुनिश्चिति की दृष्टि से, भूमि के विकास और उपयोग की योजना के लिये और विकास योजना के लिये उपबंध करता है । अतः उक्त अधिनियम संशोधित करना प्रस्तावित किया गया है ।

२. प्रस्तावित संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ निम्न अनुसार हैं :—

(एक) धारा ४०, ११३क, ११६, १२५, १२६, १२८ और १२९ में संशोधन.— उक्त अधिनियम, विकास योजना और उससे संबंधित मामलों के संदर्भ में लोक प्रयोजनों के लिये आवश्यक भूमि के अनिवार्य अर्जन के लिये उपबंध करता है । ऐसे प्रयोजनों के लिये, भूमि के अर्जन के मामले में, उक्त उपबंध, भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ (सन् १८९४ का १) के उपबंधों के संदर्भ अंतर्विष्ट है ।

भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (सन् २०१३ का ३०) अधिनियमित करने की दृष्टि से जो १ जनवरी २०१४ से प्रभावी प्रवृत्त हुआ है, उससे भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ निरसित हुआ है । परिणामतः सन् १९६६ के उक्त अधिनियम में प्रतीत भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के उपबंधों के भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ द्वारा के उपबंधों के संदर्भ प्रतिस्थापित करना इष्टकर है ;

(दो) धारा १२७ में संशोधन.—सन् १९६६ के उक्त अधिनियम की धारा १२७ यह उपबंधित करती है कि, भूमि स्वामि या भूमि में हित रखनेवाला कोई व्यक्ति, यदि भूमि, जो आरक्षित, आबंटित या अभिहित है, जिस पर अंतिम प्रादेशिक योजना, या अंतिम विकास योजना प्रवृत्त हुई है, के दिनांक से दस वर्षों के भीतर करारपत्र द्वारा अर्जित नहीं की गई है या धारा १२६ की उप-धारा (२) या (४) के अधीन अधिघोषणा ऐसी अवधि के भीतर, राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुई है, तो भूमि स्वामि या भूमि में हित रखनेवाला कोई व्यक्ति, उस प्रभाव के लिये योजना प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण या समुचित प्राधिकरण पर उसका स्वामित्व या भूमि में हित दिखानेवाले दस्तावेजों के साथ सूचना तामिल कर सकेगा और यदि, ऐसी सूचना के तामिल करने के दिनांक से बारह महिने के भीतर, भूमि अर्जित नहीं की गई या अर्जन, आरक्षण, आबंटन या अभिहित के लिये उपर्युक्त कदम नहीं उठाये गये, तो, व्यपगत समझे जायेंगे और ऐसे आरक्षण, आबंटन या अभिहित से निर्मुक्त समझी गई है ।

यह देखा गया है कि, उक्त धारा १२७ में निर्दिष्ट बारह महिने की अवधि आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति करने के लिये बहुत कम है । यह महसूस किया गया है कि, बारह महिने की, उक्त अवधि आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति करने के लिये बारह महिने की अधिकतर अवधि द्वारा विस्तारित करना आवश्यक है ।

३. उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (तृतीय संशोधन) विधेयक, २०१५, विधान मंडल के वर्षा सत्र में, २९ जुलाई २०१५ को विधानसभा का विधेयक क्र. ४४, सन् २०१५, के रूप में, महाराष्ट्र विधानसभा में पुरस्थापित किया गया था, जो १३ जुलाई २०१५ को प्रारंभ हुआ था । तथापि, उक्त विधेयक, राज्य विधानसभा का ३१ जुलाई २०१५ को सत्रावसान हो जाने के कारण, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया जा सका था । सरकार, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में, शीघ्रतम, उक्त संशोधनों को कार्यान्वित करना इष्टकर समझती है ।

४. राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ३७) में, अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है ।

मुंबई,
दिनांकित २९ अगस्त २०१५ ।

चे. विद्वत्सागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

(यथार्थ अनुवाद)

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।